शिक्षा के नाम पर हवाई गोले छोड़ते पीएम मोदी

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिल्ली में केजरीवाल सरकार द्वारा स्थापित स्कूली शिक्षा मॉडल का अत्यधिक दबाव गुजरात में, जहां तीन माह बाद चुनाव होने हैं, पड़ता देख कर प्रधानमंत्री मोदी ने भी लम्बी-लम्बी छोड़नी शुरू कर दी है। उनके लिये यह कोई नई बात नहीं है। अक्सर चुनावों के निकट आने पर वे ऐसे हथकंडे अपनाते रहे हैं। अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिये उन्होंने पीएमश्री स्कूलों को खोलने का एलान किया है। वैसे इसकी घोषणा वे एक वर्ष पूर्व करके भूल चुके थे।

मौजूदा घोषणा के अनुसार वे देश भर के कुल स्कूलों के 1 प्रतिशत को ही इस श्रेणी में लायेंगे। केवल 1 प्रतिशत ही क्यों तमाम स्कूल क्यों नहीं? शेष 99 प्रतिशत स्कूलों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? बीते आठ साल से सरकार चला रहे मोदी जी इस बाबत कुछ नहीं बताते। वे यह भी नहीं बताते कि उक्त 1 प्रतिशत स्कूल कौनसी तारीख तक चालू हो जायेंगे? क्या इसके लिये भी 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है?

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा देश भर के प्रत्येक ज़िले में जो नवोदय विद्यालय खोले गये

थे, वे भी मोदी सरकार से सम्भल नहीं पा रहे। ऐसे आधे से अधिक स्कूलों में प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं, करीब 40 प्रतिशत अध्यापकों के पद भी खाली पड़े हैं, और बात करते हैं नये स्कूल खोलने की।

फ़रीदाबाद में बदहाल सरकारी स्कूल

जनता को मूर्ख बनाने के लिये खट्टर सरकार ने झूठ के गोले दागते हुए अपने दुर्दशाग्रस्त कुछ स्कूलों का नाम बदल कर संस्कृति मॉडल स्कूल रख दिया है। इन्हें सीबीएससी से सम्बन्धित करने के साथ-साथ यहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया है। सरकार के इस चकमे में आकर शिक्षा को तरसते लोगों की भीड़ इन स्कूलों पर टूट पड़ी। दाखिलों की एक संख्या के बाद प्रिंसिपल दाखिला देने से मना कर देते हैं और सरकार ढोल पीटती है कि सबको दाखिला दिया जायेगा। लोग इसी चक्रव्यूह में चक्कर काटते रह जाते हैं।

सीबीएससी व अंग्रेजी माध्यम के नाम पर लोग यहां 500 रुपये मासिक तक की फ़ीस भरने के बावजूद शिक्षा पाने से वंचित हैं। नियमानुसार 35 बच्चों का जो सेक्शन होना चाहिये वो 60-70 तक कुछ भी हो सकता है। किसी भी स्कूल में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। चुनाव अथवा आये दिन होने वाले किसी न किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में इन शिक्षकों को झोंक देने के बाद तो स्कूल लगभग पूरी तरह से अध्यापक-रहित हो जाते हैं।

निकटवर्ती गांव मवई में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 7 अगस्त को छात्रों ने साढे नौ बजे से लेकर साढ़े 12 बजे तक, शिक्षकों की कमी को लेकर, गेट पर ताला लगा दिया। यहां छात्रों का कहना है कि छठी से आठवीं क्लास तक 193 विद्यार्थी हैं जिसमें मात्र एक संस्कृत के अध्यापक हैं। विद्यालय के हेड शिक्षक सहित एक और का तबादला कर दिया गया। चार शिक्षकों को बीएलओ (बूथ लेबल अधिकारी) लगा दिया गया। ऐसे में स्कूल में पढाने के लिये कोई अध्यापक नहीं है, यहां छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

इन छात्रों के साथ-साथ स्थानीय निवासी भी धरने में मौजूद रहे। ग्रमीणों ने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि बल्लबगढ़, उपखंड के तिगांव, पन्हेड़ा, खुर्द, चांदपुर, हीरापुर, भैंसरावली स्थित विद्यालयों में भी ऐसा ही हाल है।

ट्रक के नीचे ऑटो दबा, सभी बाल-बाल बचे

फ़रीदाबाद (म.मो.) शुक्रवार दिनांक दो सितम्बर को एक ट्रक पलट कर बगल में खड़े ऑटो रिक्शा पर जा गिरा। इत्तेफाक से उसमें सवार तीन में से दो बच्चियां पास की दुकान से टॉफी लेने चली गई थीं। ट्रक को झुकता देख कर तीसरी बच्ची व ड्राइवर भी फुर्ती से बाहर निकल गये, लेकिन निकलते-निकलते भी बच्ची का हाथ फंस कर टूट गया। कुल मिलाकर संतोषजनक यह रहा कि कोई जान नहीं गई, वरना हालात तो ऐसे थे कि चार लोग बेमौत मारे जा सकते थे।

होटल डिलाइट एनआईटी के सामने स्थित रामधर्म कांटे पर हुई इस दुर्घटना पर थाना कोतवाली ने ट्रक चालक के खिलाफ़ दुर्घटना का मुकदमा दर्ज करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ट्रक के अंदर जितनी भारी मशीन रखी हुई थी, उसके लिये ट्रक फिट नहीं था, दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रक ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा वजन लाद रखा था। इतना ही नहीं उस मशीन को दायें-बायें हिलने-डुलने से रोकने के लिये बांधा भी नहीं गया था। जाहिर है कि अवैध वाहन को सड़क पर चलने देने के लिये ट्रैफ़िक पुलिस दोषी है। यही एक ट्रक नहीं, दिन भर सैंकड़ों अवैध वाहन सड़कों पर बेखौफ़ दौड़ कर पुलिस की काली कमाई बढाते हैं।

दुर्घटना का दूसरा कारण नगर निगम द्वारा हाल ही में, सीमेंट कंक्रीट की बनाई गई अति 'मजबूत' सड़क में बन चुके गड्ढे थे। ट्रक ज्यों ही वजन करा कर धर्मकांटे से आगे बढा तो सड़क के गड्ढे में पहिया फंसने से भारी वजन वाली मशीन एक तरफ को खिसक गई जिससे वह ट्रक पलट गया।

जिस देश में प्रतिवर्ष डेढ़ लाख से अधिक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में जान गंवाते

हैं। वहां का राष्ट्रीय मीडिया एक कॉर्पोरेट हस्ती सायरस मिस्त्री की बैक सीट पर बैल्ट न लगाने को लेकर पगलाया हुआ है।

सड़क मंत्री नीतिन गडकरी को न ओवरलोडेड ट्रक दिखते हैं, न बेतहाशा रफ्तार से दौड़ती गाड़िया और न सड़कों के घटिया डिजाइन ही। इनकी वजहों से लोग सड़कों पर जान दे रहे हैं, जबकि गडकरी भी बैक सीट बैल्ट का ही रोना रो रहे हैं।

पुलिस का यह रटा-रटाया फार्मूला है कि किसी भी दुर्घटना की सूरत में बड़ी गाड़ी वाले को दोषी बना कर काम को निपटा दिया जाय। करीब चार वर्ष पूर्व बल्लबगढ़ की ओर से दिल्ली की ओर जाते हुए वधवा नामक एक स्कूटर सवार बाटा मोड़ के गड्ढों में फंस कर गिर गया था।

उसके पीछे बैठी पत्नी व बच्चा दूर जा गिरे, पीछे से आते हुए एक ट्रक ने मां-बेटे को ऐसा कुचला था कि बेटा मौके पर ही मारा गया तथा पत्नी का आज तक भी इलाज चल रहा है। उस केस में पुलिस ने ट्रक चालक का चालान करके केस को निपटा दिया था। परन्तु वधवा जी ने गड्ढों के लिये दोषी सड़क निर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बावजूद पुलिस के रवैये में कोई सुधार नहीं।

विधायक सीमा त्रिखा अध्यापकों की कमी देखने स्कूल नहीं पहुंची

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर एनएच एक नम्बर के एक निजी स्कूल में विधायक सीमा त्रिखा ने अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से इनकार किया था। इस पर '**मज़दूर मोर्चा**' संवाददाता शेखर दास ने जब एनएच तीन स्थित सीनियर सेकेन्डरी संस्कृति मॉडल विद्यालय में अध्यापकों की कमी बताई तो वे मानने को तैयार नहीं थी। '**मोर्चा**' के दावे को झूठा सिद्ध करने के लिये उन्होंने बुधवार 10 बजे शेखर दास को अपने सामने उक्त स्कूल में आने को कहा था।

शेखर तो पहुंच गये, लेकिन विधायक महोदया नहीं पहुंची। इन्हें तो पहुंचना भी नहीं था क्योंकि वे तो सच्चाई को जानती ही थी, हां झूठ बोलना उनकी सांस्कृतिक मजबूरी है। भाजपा में झूठ बोलने वाली सीमा कोई अकेली थोड़े ही हैं, झूठ बोलना तो उनका संवैधानिक दायित्व है। भाजपाई बखूबी समझते हैं कि झूठ बोलते जाओ, जब तक सच पहुंचेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। परन्तु इस मामले में तो शेखर ने देर होने नहीं दी और तुरन्त ही उक्त विद्यालय में पहुंच कर सिद्ध कर दिया कि नौवीं जमात से बारहवीं जमात तक के लिये कुल 30 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, इनमें से 19 का तबादला कर दिया गया है। अब शेष केवल 11 अध्यापक हैं जो 800 बच्चों को पशुओं की तरह बाड़े में घेर कर रखेंगे।

इसी तरह छठी जमात से आठवीं तक के 300 बच्चों के लिये 10 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से एक भी तैनात नहीं है। काम चलाने के लिये यानी जनता को बहकाने के लिये अस्थायी तौर पर मात्र दो गेस्ट अध्यापक रखे गये हैं। इन तथाकथित मॉडल स्कूलों के लिये 30 बच्चों का एक सेक्शन बनाना चाहिये लेकिन यहां तो किसी भी सेक्शन में 50 से कम बच्चे नहीं हैं। यह बदहाली तो खट्टर सरकार के उन मॉडल स्कूलों की है जिनके लिये सरकार अपनी पीठ थपथपाती नहीं अघाती। इतना ही नहीं इन स्कूलों में दाखिला भी बड़ी सिफ़ारिशों से मिलता है और फ़ीस भी 500 रुपये मासिक हैं। इस सबके बावजूद हालात पाठकों के सामने हैं।

शेष बचे उन हजारों सरकारी स्कूलों की बदहाली क्या होगी उसका अंदाजा पाठक स्वयं लगा सकते हैं। अब ऐसे स्कूलों में कोई अपने बच्चों को भेजे तो क्यों भेजे? वे कोई भेड़-बकरी तो हैं नहीं जिन्हें बाड़े में घेर कर बैठाये रखने के लिये 'स्कूल' भेजा जाये। ऐसे हालात में ज्यों ही बच्चे स्कूल आना बंद करते हैं तो सरकार को स्कूल बंद करने का बहाना मिल जाता है। एनएच तीन के उक्त मॉडल स्कूल में भी जब बच्चे आना बिल्कुल बंद कर देंगे तो सरकार इसे औने-पौने में किसी शिक्षा व्यापारी को बेच देगी

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।